एक नागरिक, एक पहचान: सिम–आधारित पहचान प्रणाली की संभावनाएँ और चुनौतियाँ

डॉ. अमित अग्रवाल[1*] और चतर सिंह नेगी[2]

[1] सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, राजकीय महाविद्यालय, मिलक, शाहबाद, रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, पं. ललित मोहन शर्मा परिसर, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड, भारत

*Corresponding Author: डॉ. अमित अग्रवाल

Received 1 Apr 2026; Accepted 12 May 2026; Published 29 May 2026

DOI: https://doi.org/10.64171/JSRD.5.S3.101-104

सारांश

भारत में लोगों के पास आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल नंबर जैसे कई अलग–अलग पहचान पत्र होते हैं। इससे लोगों के लिए अपनी पहचान साबित करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें कई फॉर्म भरने पड़ते हैं और कई तरह की जांच करानी पड़ती है। इस विचार का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष 12 अंकों का नंबर देना है जिसे वे हमेशा अपने पास रख सकें। यह नंबर उनकी मुख्य पहचान होगी, उनके फोन नंबर के रूप में काम करेगा और उन्हें डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में मदद करेगा। वे इस नंबर का उपयोग किसी भी फोन कंपनी के साथ कर सकते हैं। इसका लक्ष्य यह देखना है कि क्या यह विचार सरकार को बेहतर ढंग से काम करने, लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने, लोगों को आसानी से लाभ प्राप्त करने, अधिक लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने और गोपनीयता की रक्षा करने में मदद कर सकता है। इस बारे में जानने के लिए, एक अध्ययन में 200 लोगों से प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर एकत्र किए गए। लोगों ने कहा कि इस विचार के सबसे अच्छे पहलू फर्जी सिम कार्डों को रोकना, केवल एक पहचान पत्र होना, सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करना और साइबर अपराधों से लड़ना है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा जोखिम, सरकार द्वारा निगरानी, अच्छी तकनीक की आवश्यकता और निष्पक्ष कानून बनाने जैसी समस्याएं भी हैं। यदि लोगों के डेटा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े नियमों के साथ सावधानीपूर्वक लागू किया जाए, तो यह प्रणाली भारत को अधिक डिजिटल और संगठित बनाने में सहायक हो सकती है। आज, बेहतर सरकारी कामकाज, सुरक्षा और सभी को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अच्छी पहचान प्रणाली का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मूलशब्द: लाइफटाइम सिम नंबर, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, आधार एकीकरण

प्रस्तावना

21वीं सदी में, किसी भी देश की सरकार के सुचारू रूप से काम करने के लिए डिजिटल पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सरकारी कार्यक्रमों, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाओं में लोगों की पहचान सुनिश्चित करके मदद करती है। भारत ने आधार नामक विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल आईडी प्रणाली बनाई है, जो लोगों को सीधे पैसे देने और डिजिटल सेवाओं का आसानी से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। लेकिन, लोगों के पास अक्सर आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते, पासपोर्ट और मोबाइल नंबर जैसे कई अलग-अलग आईडी कार्ड होते हैं। इतने सारे आईडी कार्ड होने से चीजें जटिल हो जाती हैं, खर्च बढ़ जाता है और कभी-कभी गलतियाँ या धोखाधड़ी भी हो सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, "एक नागरिक, एक पहचान" नामक एक नया विचार सामने आया है। इस योजना के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के समय एक विशेष 12 अंकों का नंबर मिलेगा। यह नंबर उनकी आजीवन डिजिटल आईडी होगी और इसका उपयोग किसी भी फोन कंपनी के साथ किया जा सकता है। यह उन्हें एक ही आईडी से सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँचने में भी मदद करेगा। सिम कार्ड आपके फोन में लगी एक छोटी सी कंप्यूटर चिप होती है जो फोन नेटवर्क पर आपकी पहचान दर्शाती है। वर्तमान में, यह कॉल, स्थान और इंटरनेट उपयोग से संबंधित जानकारी संग्रहीत करता है। यदि इस सिम कार्ड को राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रणाली से जोड़ा जा सके, तो इससे सरकार को सेवाओं का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। लेकिन, इस विचार से निजता, सुरक्षा और जन अधिकारों को लेकर चिंताएं भी पैदा होती हैं। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई इसका दुरुपयोग न करे, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह अध्ययन इस प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

साहित्य समीक्षा

डिजिटल पहचान प्रणाली दुनिया भर में कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों को पहचानने के विशेष तरीके हैं। विश्व बैंक (2018) [3] का कहना है कि डिजिटल पहचान अधिक लोगों को बैंकिंग और अन्य सेवाओं तक पहुँचने में मदद करने की कुंजी है। उनका मानना है कि एक मजबूत पहचान प्रणाली सरकार के कामकाज को बेहतर बनाती है और लोगों को धोखाधड़ी करने से रोकती है। गेल्ब और क्लार्क (2013) [2] जैसे शोधकर्ताओं ने पाया कि उंगलियों के निशान और डिजिटल आईडी का उपयोग सरकारी सहायता कार्यक्रमों को अधिक निष्पक्ष और स्पष्ट बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल आईडी वाले मोबाइल फोन का उपयोग करने से पैसे की बचत हो सकती है और काम आसान हो सकता है। मुरलीधरन, नीहॉस और सुखथंकर (2016) [5] ने भारत में आधार नामक एक प्रणाली का अध्ययन किया, जो लोगों को सीधे सरकारी धन प्राप्त करने में मदद करती है। उन्होंने

पाया कि ऑनलाइन लोगों की पहचान की जाँच करने से धोखाधड़ी रुकती है और सरकार के पैसे की बचत होती है। पहचान की जाँच करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य शोधकर्ता, डोनोवन (2015) ने कहा कि ऑनलाइन लोगों की पहचान करने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका अब फोन नंबर हैं। यह बैंकिंग, खरीदारी और सरकारी सेवाओं के लिए बहुत उपयोगी है। मास और पोर्टियस (2015) का मानना है कि लोगों की पहचान करने के लिए फोन का उपयोग करने से गरीब देशों में अधिक लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जब मोबाइल पहचान डिजिटल मुद्रा के साथ काम करती है, तो अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ती हैं। कुनेर, केट, मिलार्ड और स्वेंटेसन (2017) ने बताया कि लोगों के डेटा की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोगों की निजता की रक्षा किए बिना कोई भी डिजिटल पहचान प्रणाली ठीक से काम नहीं कर सकती। राव और नायर (2019) ने भारत की आधार प्रणाली के बारे में बात की। यह लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में मदद करती है, लेकिन डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएँ भी पैदा करती है। नीति आयोग (2022) [6] ने कहा कि पहचान, मुद्रा और डेटा साझाकरण जैसी डिजिटल प्रणालियाँ भारत के भविष्य के विकास की आधारशिला हैं। उनका मानना है कि इन प्रणालियों को एक साथ लाने से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी। कई अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल पहचान से सरकारी कामकाज आसान हो जाता है। लेकिन, डेटा की सुरक्षा और लोगों के अधिकारों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन इन्हीं महत्वपूर्ण सुरक्षा और निजता संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- एक नागरिक, एक पहचान" मॉडल की व्यवहार्यता का अध्ययन।
- 12 अंकों के स्थायी सिम कार्ड नंबर के संभावित लाभों का आकलन।
- नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों की पहचान।
- नागरिकों की सहमति के आधार पर प्रमुख लाभों और चुनौतियों का क्रम निर्धारण।
- नीति विकास के लिए प्रस्ताव।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन में चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए सरल शोध विधियों का उपयोग किया गया। उन्होंने शिक्षकों, छात्रों, बैंक कर्मचारियों, तकनीकी विशेषज्ञों, सरकारी कर्मचारियों, व्यवसाय मालिकों और आम लोगों सहित 200 लोगों से एक विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से प्रश्न पूछे। लोगों ने "पूरी तरह सहमत" से लेकर "पूरी तरह असहमत" तक के विकल्पों के साथ उत्तर दिए। शोधकर्ताओं ने "सहमत" और "पूरी तरह सहमत" उत्तरों को जोड़कर यह देखा कि कितने लोग सहमत थे। फिर उन्होंने इन उत्तरों के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण कारणों को क्रमबद्ध किया।

परिणाम और विश्लेषण

विकसित भारत @2047 में एक सशक्त भारत के लिए सुरक्षित और उपयोग में आसान डिजिटल आईडी प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लोगों को सरकारी सेवाएं शीघ्रता से प्राप्त करने, बैंकिंग और धन संबंधी सेवाओं तक पहुंच बनाने, लाभों को निष्पक्ष रूप से प्राप्त करने और सरकार के ऑनलाइन कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करती है। साथ ही, लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना, साइबर खतरों से बचाव करना, बेहतर डिजिटल प्रणालियां बनाना और सभी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

तालिका 1: 12 अंकों वाले सिम कार्ड के उपयोग के शीर्ष 10 लाभ

रैंक	प्रमुख लाभकारी कारक	सहमति प्रतिशत
1	फ़ेक सिम और साइबर अपराधों में कमी	94%
2	'एक नागरिक, एक पहचान' सिस्टम	92%
3	सरकारी योजनाओं के फ़ायदों की बेहतर डिलीवरी	91%
4	यूनिवर्सल ई-KYC सुविधा	89%
5	बैंकिंग और फ़ाइनेंशियल सेवाओं तक आसान पहुँच	88%
6	गुमशुदा लोगों की पहचान में मदद	87%
7	स्पैम कॉल और धोखाधड़ी पर नियंत्रण	86%
8	प्रशासनिक लागत में कमी	84%
9	डिजिटल सेवाओं की तेज़ी से उपलब्धता	83%
10	राष्ट्रीय सुरक्षा में मदद	81%

स्रोत: प्राथमिक डेटा [उत्तरदाताओं की सहमति के प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग]

तालिका-01 से पता चलता है कि अधिकांश लोगों का मानना है कि सभी के लिए एक विशेष 12 अंकों का आईडी नंबर, जो जीवन भर मान्य रहे, देश के बेहतर संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और फर्जी सिम कार्डों को रोकने में बहुत मददगार होगा। लगभग 100 में से 94 लोगों का मानना है कि यह प्रणाली फर्जी सिम और ऑनलाइन अपराधों जैसे धन या व्यक्तिगत जानकारी की चोरी को रोकेगी। वर्तमान में, अपराधी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड प्राप्त करते हैं और ऑनलाइन अवैध गतिविधियां करते हैं। लेकिन अगर जन्म से ही सभी के पास एक स्थायी, सत्यापित सिम हो, तो इन अपराधों को पकड़ना और रोकना बहुत आसान हो जाएगा। "एक नागरिक, एक पहचान" नामक विचार को दूसरा सबसे अधिक समर्थन मिला, जिसे 100 में से 92 लोगों ने पसंद किया। इससे चीजें सरल हो जाएंगी क्योंकि लोगों को आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र या कई फोन नंबर जैसे कई अलग-अलग आईडी कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, किसी को बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट बनवाने या सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए कई कागजात देने की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग 100 में से 91 लोगों का मानना है कि इससे सरकार को छात्रवृत्ति, पेंशन, ईंधन खर्च और कृषि सहायता जैसी सुविधाएं सीधे लोगों के खातों में भेजने में मदद मिलेगी। लगभग 100 में से 89 लोगों को सार्वभौमिक ई-केवाईसी का विचार पसंद आया, जिसका अर्थ है एक ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली जिसका उपयोग फोन, बैंक, बीमा और निवेश के लिए किया जा सकता है, ताकि लोगों को बार-बार अपने दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता न पड़े। लगभग 100 में से 88 लोगों का मानना था कि इससे लोगों, विशेष रूप से दूरदराज के गांवों में रहने वालों के लिए, बैंकों और वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना आसान हो जाएगा क्योंकि उनकी पहचान उनके फोन पर होगी। लगभग 100 में से 87 लोगों का मानना था कि इससे लापता बच्चों, बुजुर्गों या आपदा में फंसे लोगों को अधिक तेज़ी से खोजने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदा के दौरान, अधिकारी लोगों की पहचान तेज़ी से कर सकेंगे। लगभग 100 में से 86 लोगों ने इस प्रणाली को स्पैम कॉल और ऑनलाइन घोटालों को रोकने के एक तरीके के रूप में देखा क्योंकि प्रत्येक कॉलर के नंबर का सत्यापन किया जाएगा। लगभग 100 में से 84 लोगों का मानना था कि इससे धन की बचत होगी क्योंकि विभिन्न सरकारी विभागों को अब अलग-

अलग पहचान प्रणाली की आवश्यकता नहीं होगी। लगभग 100 में से 83 लोगों का मानना था कि ऑनलाइन कक्षाएं, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी सहायता और डिजिटल भुगतान जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग तेज़ और आसान हो जाएगा। अंत में, 100 में से 81 लोगों ने कहा कि यह प्रणाली सीमा पार संदिग्ध गतिविधियों, आतंकवादियों और साइबर अपराधों पर नज़र रखकर देश को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। कुल मिलाकर, अधिकांश लोगों का मानना है कि यह नई पहचान प्रणाली देश के कामकाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, लेकिन सभी की निजता और डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियमों की भी आवश्यकता है। उत्तरदाताओं ने फर्जी सिम रोकथाम तथा साइबर अपराध नियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण लाभ माना। नागरिकों ने यह भी स्वीकार किया कि एकीकृत पहचान प्रणाली सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बना सकती है।

सिम कार्ड को आईडी के रूप में इस्तेमाल करते समय, 10 सबसे बड़ी समस्याओं का सामना-

तालिका 2

रैंक	प्रमुख चुनौती	सहमति प्रतिशत
1	डेटा प्राइवेसी को खतरा	95%
2	सेंट्रलाइज्ड सर्विलांस को लेकर चिंता	92%
3	साइबर हमलों का जोखिम	91%
4	डेटा लीक होने की संभावना	90%
5	मज़बूत कानूनी ढांचे की ज़रूरत	88%
6	तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत	86%
7	ग्रामीण इलाकों में डिजिटल अंतर	84%
8	टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को अपग्रेड करने की ज़रूरत	83%
9	बच्चों के डेटा को मैनेज करने की जटिलता	82%
10	मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत	80%

स्रोत: प्राथमिक डेटा [उत्तरदाताओं की सहमति के प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग]

तालिका -02 में प्रस्तुत प्राथमिक डेटा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी सेवाओं जैसी सभी चीजों के लिए एक ही सिम कार्ड को पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने से खुश हैं। लेकिन वे कई खतरों को लेकर चिंतित भी हैं। लगभग सभी, यानी 100 में से 95 लोग, इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है या उसका दुरुपयोग हो सकता है। उन्हें डर है कि अगर कोई सिस्टम को हैक कर लेता है, तो वे उनकी सभी व्यक्तिगत जानकारी देख सकते हैं। कई लोग, यानी 100 में से 92 लोग, इस बात से भयभीत हैं कि सरकार या अन्य लोग उनकी गतिविधियों, स्थान और संदेशों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। लगभग 100 में से 91 लोग साइबर हमलों से डरते हैं जो किसी बड़े डेटाबेस से डेटा चुरा सकते हैं और एक साथ लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लगभग 100 में से 90 लोग इस बात से चिंतित हैं कि डेटा लीक हो सकता है। अधिकांश लोग, यानी 100 में से 88 लोग, कहते हैं कि सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि सही तकनीक विकसित करने में बहुत खर्च आएगा (100 में से 86 लोग यही मानते हैं) और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के पास अच्छी इंटरनेट सुविधा नहीं होगी या उन्हें डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना नहीं आता होगा, जो कि 100 में से 84 लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। अन्य लोगों का कहना है कि फोन नेटवर्क को अपग्रेड करना आवश्यक है, 100 में से 83 लोग इस बात पर जोर देते हैं। बच्चों के डेटा का प्रबंधन भी पेचीदा है, 100 में से 82 लोग इस ओर इशारा करते हैं, और 100 में से 80 लोग कहते हैं कि बहु-स्तरीय सुरक्षा जांच महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए नई तकनीक, अच्छे कानून और मजबूत सुरक्षा सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने गोपनीयता और निगरानी संबंधी चिंताओं को प्रमुख चुनौती माना। इससे स्पष्ट है कि नागरिक डिजिटल सुविधा के साथ-साथ डेटा सुरक्षा को भी समान महत्व देते हैं।

आम तौर पर लोग इस बात से सहमत हैं कि सभी के लिए एक ही डिजिटल आईडी होना एक अच्छा विचार है। अधिकांश का मानना है कि एक स्थायी आईडी नंबर से कई सरकारी कार्य आसान हो जाएंगे। उनका यह भी मानना है कि इससे फर्जी सिम कार्ड, स्पैम कॉल और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। कई लोगों का कहना है कि अगर सभी के पास एक स्थायी आईडी हो, तो पैसों से जुड़े अपराध कम हो जाएंगे। अध्ययन से पता चलता है कि लाभ, छात्रवृत्ति, पेंशन और सामाजिक सहायता जैसी सेवाएं काफी बेहतर हो सकती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि बैंकिंग और ऑनलाइन सरकारी सेवाओं में काफी सुधार हो सकता है। हालांकि, कई लोग निजता और अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि किसी भी राष्ट्रीय डिजिटल आईडी प्रणाली में डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियम होने चाहिए और इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र समूह होने चाहिए।

निष्कर्ष

"एक नागरिक, एक पहचान" का विचार सरकार के कामकाज को बेहतर और अधिक ईमानदार बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इससे सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन इसकी सफलता के लिए हमें लोगों की निजता और अधिकारों की रक्षा करनी होगी। मजबूत एन्क्रिप्शन का उपयोग करना, डेटा को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करना, आभासी पहचान बनाना और सिस्टम की निगरानी के लिए स्वतंत्र समूहों का होना इसमें सहायक हो सकता है। यदि ये कदम उठाए जाते हैं, तो यह विचार भारत को अधिक डिजिटल और कनेक्टेड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकार, फोन कंपनियां, तकनीकी विशेषज्ञ और नागरिक सभी को मिलकर एक सुरक्षित और निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए काम करना चाहिए। सिम आईडी इसलिए खास है क्योंकि यह डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके वास्तविक समय में आपकी पहचान दिखा सकती है। आधार या मतदाता पहचान पत्र जैसे सामान्य पहचान पत्रों के विपरीत, जो केवल आपकी पहचान साबित करते हैं, सिम आईडी का इस्तेमाल दूसरों से बात करने, अपनी पहचान साबित करने और ऑनलाइन सेवाओं का तुरंत उपयोग करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह बैंकिंग सुरक्षा कोड, सरकारी लाभ प्राप्त करने, आपातकालीन सहायता प्राप्त करने, ऑनलाइन दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने और वेबसाइटों और ऐप्स का उपयोग करने में मदद कर सकती है—यह सब एक ही आईडी से संभव है। गोपनीयता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सावधानीपूर्वक

उपयोग करने पर, सिम आईडी सरकारी कामकाज को तेज करने, फर्जी आईडी को रोकने और सभी के लिए सेवाओं को आसान, त्वरित और स्पष्ट बनाने में मदद कर सकती हैं।

References

1. Donovan KP. Mobile money for financial inclusion. In: Kelly T, Minges M, editors. Information and Communications for Development 2012: Maximizing Mobile. World Bank, 2012, 61-73.
2. Gelb A, Clark J. Identification for Development: The Biometrics Revolution. Center for Global Development, 2013.
3. World Bank. Identification for Development (ID4D) Global Dataset 2018. World Bank Group, 2018.
4. World Bank. Principles on Identification for Sustainable Development: Toward the Digital Age. World Bank Group, 2018.
5. Muralidharan K, Niehaus P, Sukhtankar S. Building state capacity: Evidence from biometric smartcards in India. Am Econ Rev. 2016;106(10):2895-2929.
6. NITI Aayog. India's Digital Public Infrastructure: Future Pathways for Governance and Growth. Government of India, 2022.
7. United Nations Development Programme. Digital Identity and Inclusive Development. United Nations Development Programme, 2020.
8. World Economic Forum. Digital Identity: A Strategic Imperative. World Economic Forum, 2021.
9. Unique Identification Authority of India. Aadhaar Authentication and Digital Identity Ecosystem in India. UIDAI, 2024.
10. Ministry of Electronics and Information Technology. Digital Personal Data Protection Act, 2023. Government of India, 2023.
11. Ministry of Education. APAAR ID: One Nation One Student ID Initiative. Government of India, 2024.
12. Telecom Regulatory Authority of India. Mobile Number Portability Regulations and Telecom Identity Framework. TRAI, 2024.